

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफ़ैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/CBuD/2023/37874-38115

दिनांक :- 02/06/2023

1. मुख्य अभियन्ता,
आरयूआईडीपी, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक (इन्फ्रा/हाउसिंग)
रूडसिको, जयपुर।
3. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।

विषय :- सड़को/सीवरेज व अन्य के निर्माण/विकास कार्यों के दौरान सड़कों की खुदाई से पूर्व सूचना Call before U Dig (CBuD) Mobile App पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त ईमेल दिनांक 01.06.2023 तथा सूचना एवं संचार विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक 02351/2023 दिनांक 03.05.2023 के क्रम में।

सड़को एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुदाई के दौरान विभिन्न आवश्यक सेवाओं, पाईप लाईन, पावर केबल, ओ.एफ.सी केबल इत्यादि के क्षतिग्रस्त हो जाने एवं जनमानस को होने वाली असुविधा के निराकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर “Call before U Dig” Mobile App का शुभारम्भ किया गया है। Mobile App से सभी आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभाग एवं विकास कार्य वाले विभागों को जोड़ा गया है तथा सड़क या सार्वजनिक स्थल पर किये जाने वाले खुदाई कार्य की सूचना Mobile App पर डाली जाकर विभागों की अनापत्ति (NOC) होने पर ही कार्य किया जा सकेगा।

DoT द्वारा Indian telegraph (infrastructure safety) rules 2022 का प्रकाशन भारत का राजपत्र दिनांक 03.01.2023 में किया गया है (प्रति संलग्न)। जिसके अनुसार “It is mandates to use portal or mobile app and casting liability on excavator/excavation agencies to notify any likely excavation through the app to the telegraph/telecom licensee owning or managing telegraph infrastructure. Any damages caused due to negligence and liable to pay damage charges. CBuD app is supported by these provisions” का प्रावधान किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन चल रहे एवं भविष्य में किये जाने वाले विभिन्न विकास/निर्माण कार्यों की कार्यकारी संस्था एवं संवेदक/फर्मों को उक्त मोबाईल एप्प पर रजिस्टर्ड करवाया जाकर सड़को की खुदाई से पूर्व एप्प पर सूचना अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

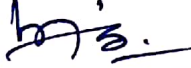
(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/CBuD/2023/38116-130

दिनांक :- 02/06/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (DoIT/Revenue), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, उप निदेशक जनरल (ग्रामीण), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, आयुक्त, DoIT, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके क्षेत्राधिकार की शेष निकायों को 03 दिवस में मोबाईल एप्प पर रजिस्टर्ड किया जाकर, उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(महेन्द्र कुमार माथुर)
मुख्य अभियन्ता

To carry out any type of excavation/ digging only after prior intimation through CBUd Mobile App

1 message

Vinod Kumar Gupta <adr1.rj-dgt-dot@gov.in>

1 June 2023 at 12:33

To: tulsigurjardoit <tulsigurjar.doit@rajasthan.gov.in>, cehq <cehq@jvvn1.org>, cedlbjp <cedlbjp@gmail.com>, rajprsep <rajpr.sep@rajasthan.gov.in>, rj_cehq <rj_cehq@nic.in>, seroad <seroad@rediffmail.com>, bataranita <batar.anita@gmail.com>

Cc: manojkumar doit <manojkumar.doit@rajasthan.gov.in>, ashishkg doit <ashishkg.doit@rajasthan.gov.in>, secretary itc <secretary.itc@rajasthan.gov.in>, SUNIL SINGHAL <dir2r2.rj-dgt-dot@gov.in>, V K Surendra <ddgr1.rj-dgt-dot@gov.in>

To,

All department Nodal Officers for CBUd Mobile App,

1. Energy Department
 2. Local Self-Government Department
 3. Panchayati Raj
 4. Public Works Department
 5. WRD
 6. DoIT
 7. PHED
- Govt. of Rajasthan.

With reference to DoIT, Govt. of Rajasthan letter dated 03.05.2023 (Copy of letter attached), you are requested to arrange for issuing the directions to excavating agencies of your respective department to onboard themselves on CBUd app and carry out any type of excavation/ digging work only after prior notification through CBUd app.

In this regard, Gazette notification issued dated 03.01.2023 also attached for ready reference.

Vinod Kumar Gupta
JTO (Rural) O/o Additional Director General Telecom,
Rajasthan LSA, Jaipur.
Sanchar Bhawan, Jhalana Institutional Area,
Deptt. of Telecom, Govt. of India
Jaipur-302004
M. 9413395714

2 attachments

DoIT letter dated 03.05.2023 to department regarding mandation CBUd app before excavation activity.pdf
867K



Gazette Notification -ITIS Rules-03-01-2023.pdf
1445K

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

No:- F8(431)/DoIT/Gen/21/02351/2023

Dated :- 03/05/2023

To,

State Department Nodal Officer

Call Before u Dig (CBuD) Mobile app

UDH/LSG/PHED/Energy/PWD/Panchayati Raj/ Water Resources department

Government of Rajasthan, Jaipur

Subject: - To carry out any type of excavation/ digging only after prior intimation through CBuD Mobile App.

Reference: - 1. D.O. letter to CS (GoR) vide ref. no. 3-1/2022-NBM dated 07-02-2023.
2. Letter to departments vide ref. no:-F8(431)DoIT/Gen/21/00107/2023 dated :-04-01-2023

Sir/Madam,

In reference to above cited subject and references, I would like to thank for your effort regarding onboarding the contact detail of all concerned officials of infrastructure utility asset owner agencies of your respective department in CBuD App to receive notifications of the enquiries made by other agencies/contractors/members of public likely to undertake excavation activities in public enabling them to safeguard the assets from damages during excavator.

In this regard, it is also bring to you notice that DoT has issued "Indian telegraph (infrastructure safety) rules, 2022" (ITIS Rules, 2022) on 03rd January 2023, which mandates to use portal or mobile app and casting liability on excavator/excavation agencies to notify any likely excavation through the app to the telegraph/telecom licensee owning or managing telegraph infrastructure. Any damages caused due to negligence and liable to pay damage charges. CBuD app is supported by these provisions.

In continuation to this, Secretary (Telecom), DoT (GoI) is requested to state government (vide DO ref no 3-1/2022-NBM dated 7th February, 2023) to instruct all excavating agencies to onboard themselves on CBuD app.

Therefore, it is requested you to arrange for issuing the directions to excavating agencies of your respective department to onboard themselves on CBuD app and carry out any type of excavation/ digging work only after prior notification through CBuD app. A sample list of excavating agencies which are required to be on-boarded on CBuD app is attached as annexure -A for your ready reference.

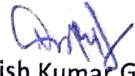
Enclosed: - Annexure-A.


(C. P. Singh)
GM (Tech)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

Copy to following for information:

1. PS to Chief Secretary, GoR
2. PS to Add. Chief Secretary, PHED
3. PS to Add. Chief Secretary, IT&C
4. PS to Add. Chief Secretary, Water Resources
5. PS to Pr. Secretary, UDH
6. PS to Pr. Secretary, Energy
7. PS to Pr. Secretary, PWD
8. PS to Secretary, Panchayati Raj
9. PS to Secretary, LSG
10. PS to Commissioner, IT&C
11. Sr.DDG, DoT, LSA, Rajasthan


(Ashish Kumar Gupta)
Jt. Director, DoIT&C



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241640
CG-DL-E-03012023-241640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]
No. 05]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2023/पौष 13, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2023/ PAUSHA 13, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 06(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) “अधिनियम” से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) “सामान्य पोर्टल” से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित और अधिसूचित पोर्टल या मोबाइल फ्रोन उपयोजन अभिप्रेत है;

(ग) “अनुज्ञप्तिधारी” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) “सूचना” से सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की गई खुदाई या उत्खनन संबंधी पूर्व सूचना अभिप्रेत है;

(ड.) “तार अवसंरचना” में तार या तार लाइन और पोस्ट शामिल हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. किसी संपत्ति की खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया – (1) कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति के अधिकार के विधिक अधिकार से खुदाई या उत्खनन की इच्छा इस प्रकार से रखता हो जिससे कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से स्थापित की गई तार अवसंरचना या टेलीग्राफिक संचार को रुकावट डालने या बाधित करने की संभावना हो, तो वह व्यक्ति ऐसे अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व इस प्रकार की खुदाई या उत्खनन की सूचना, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करके अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना में विधिक अधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम और पता, एजेंसी का ब्यौरा, पता, खुदाई शुरू करने की तारीख और समय, खुदाई का विवरण और स्थान तथा इस प्रकार की खुदाई या उत्खनन करने के कारण शामिल किए जाएंगे।

(3) अनुज्ञप्तिधारी उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने पर संपत्ति से संबंध किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित या तार अवसंरचना का ब्यौरा सामान्य पोर्टल के माध्यम से यथा शीघ्र उपलब्ध कराएगा जिसका प्रयोग वह तार अवसंरचना को क्षति पहुँचाए बिना समन्वय के लिए पूर्वावधानी उपायों के साथ-साथ अधिकार के विधिक प्रयोग के लिए करना चाहता है।

(4) खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, उप-नियम (3) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए पूर्वावधानी उपायों पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

(5) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 19(क) के अनुसार विहित समय के भीतर ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराता है तो खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति इसके पश्चात संपत्ति की खुदाई या उत्खनन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. नियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए नुकसानी प्रभार – (1) कोई व्यक्ति, जिसने किसी संपत्ति की खुदाई या उत्खनन के विधिक अधिकार का प्रयोग इस ढंग से किया हो, जिससे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विधिवत रखे गए तार अवसंरचना के बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, वह तार प्राधिकारी को नुकसानी प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नुकसानी प्रभार की गणना ऐसे खर्चों के आधार पर की जाएगी जैसा नुकसानी के प्रत्यावर्तन में उपगत किया जाए।

[फा. सं. 2-16/2022- नीति]

आनंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2023

G.S.R. 06(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Telegraph (Infrastructure Safety) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** -(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- (b) “common portal” means a portal or mobile phone application developed and notified by the Central Government for the purposes of these rules;
- (c) “licensee” means any person holding a license under sub-section (1) of section 4 of the act.
- (d) “notice” means prior information of digging or excavation submitted through common portal.
- (e) “telegraph infrastructure” includes a telegraph or a telegraph line and post;

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. **Procedure for exercising of legal right to dig or excavate any property.** — (1) Any person desiring to dig or excavate in the legal exercise of a right with any property in such a manner as is likely to cause damage to a telegraph infrastructure or to interrupt or interfere with telegraphic communication which has been duly placed in accordance with the provisions of the Act, shall give notice to licensee through common portal, by submitting the information of such digging or excavation, prior to the commencement of such exercise.

(2) The notice under sub-rule (1) shall include the name and address of the person exercising the legal right, agency details, contact details, date and time of start of the exercise, description and location of the exercise, and the reasons for such digging or excavation.

(3) The licensee shall, on submission of notice by the person under sub-rule (1), as expeditiously as possible provide through the common portal, the details of telegraph infrastructure owned or control or managed by such licensee, falling under or over or along the property with which the person intends to deal in legal exercise of the right, along with precautionary measures for coordination in avoiding damages to the telegraph infrastructure.

(4) The person exercising legal right to dig or excavate shall take appropriate action on precautionary measures provided by the licensee as per sub-rule (3).

(5) In case no licensee provides details within the prescribed time as per section 19(A) of the Act, the person having legal right to dig or excavate shall be free to dig or excavate the property thereafter.

4. **Damage charges for breach of provisions of the rule.** — (1) Any person, who in exercise of legal right has dug or has excavated any property in such a manner causing damage to a telegraph infrastructure duly placed in accordance with the provisions of the Act shall be liable to pay the damage charges to the telegraph authority:

(2) The damage charges under sub-rule (1) shall be computed based on such expenses as may be incurred in restoring damages.

[F. No. 2-16/2022-Policy]

ANAND SINGH, Jt. Secy.